

TURE be pleased to state the steps proposed by Government to ensure adequate area of land under foodgrain crops and to check diversion of land from foodgrain crops to commercial crops with a view to achieve self-sufficiency in food production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): The programmes for agricultural production envisage simultaneous increase of production of both foodgrain and commercial crops mainly through intensive cultivation measures designed to increase yield per acre. The production policies including price and other incentives are designed to achieve this objective. No diversion of area from foodgrains to commercial crops or *vice versa* is envisaged.

#### Procurement and Storage of Foodgrains

\*1194. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether he has seen reports in the Press that the foodgrain dealers are carrying on a propaganda that Government have no capacity of storage and would not be able to purchase surplus foodgrains from markets ;

(b) whether he has also seen reports that the foodgrain dealers are telling farmers that Government would not guarantee minimum prices so that they are able to enter into advance agreements at a far lower price ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) Reports in the press have come to the notice of Government that there is no adequate storage capacity to enable Govt. to make full purchase of surplus rabi crop. But Govt. have no

information that these reports were inspired by foodgrain dealers.

(b) A stray report from Madhya Pradesh has come to Government's notice.

(c) There is adequate storage capacity available to the Government to meet this year's anticipated requirements. Government have also announced that they will be prepared to purchase all foodgrains offered to them for sale at the procurement prices. The State Government have also been advised to give wide publicity to the fact that all foodgrains offered at the procurement prices will be purchased by the Food Corporation of India or other Governmental agencies.

#### भारत में उर्वरकों की मांग

\*1195. श्री श्री० प्र० त्यागी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी आयातित उर्वरकों के मूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में करती है अथवा क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत भी उर्वरक प्राप्त होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत को रुपये में भुगतानी के आधार पर उर्वरक सप्लाई करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार सन्मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पी० एल० 480 सहयता के अन्तर्गत उर्वरक प्राप्त नहीं किये जाते हैं। उधार और ऋण को जिनसे उर्वरकों के अग्रयातों में घटन लगाया जाता है विदेशी मुद्रा में अदा किया जाता है। जहाँ तक पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात का सम्बन्ध है यद्यपि यह अदायगी अपरिवर्तनीय रूपों में की जाती है, फिर भी इन देशों के रुपये लेखे में उस उधार को जमा करके सामान के निर्यात से समतुलित करना पड़ता है।

(ख) जो देश वस्तु-विनियम के आधार पर व्यापार योजना उपबन्धों के अन्तर्गत रूपों

में भारत को उर्वरक सप्लाई कर रहे हैं वे निम्न हैं :-

- 1 — रूस
- 2 — जर्मन गणराज्य संघ
- 3 — बुल्गारिया
- 4 — रूमानिया
- 5 — हंग्री
- 6 — पोलैंड ।

#### असिंचित क्षेत्र

\*1196. श्री देवराव पाटिल : क्या कृषि तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असिंचित क्षेत्रों और वहां पर बोई नई फसलों के सर्वेक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्डे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

#### विबरण

प्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न का सम्बन्ध भूमि सर्वेक्षण की उस योजना से है जिसके अन्तर्गत एक क्षेत्र की मिट्टी का उसकी विशेषता जानने के लिए अध्ययन किया जाता है और उसकी क्षमता के आधार पर कृषि तथा अन्य प्रयोजनों हेतु उसके प्रयोग के लिए उसकी व्याख्या की जाती है । यद्यपि केवल मात्र असिंचित क्षेत्रों के लिए भूमि सर्वेक्षण करने के लिये कोई विशेष योजना नहीं है तथापि सर्वेक्षण होने वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का समावेश सम्यक् रूप से कर लिया जाता है और असिंचित क्षेत्रों के लिए भी मिट्टी व भूमि उपयोग के मानचित्र तैयार किये जाते हैं । मौजूदा भूमि के उपयोग और सर्वेक्षण हुए क्षेत्रों में उगाई गई फसलों से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़े भी एकत्रित किये जाते हैं ।

अखिल भारतीय मिट्टी व भूमि उपयोग सर्वेक्षण की एक केन्द्रीय स्कीम है जिसके अन्तर्गत

मुख्यतः भूमि संरक्षण योजनाओं की तैयारी हेतु उपयोग में लाये जाने वाले मिट्टी व भूमि उपयोग के मानचित्र तैयार करने के लिये चुनी हुई नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रह क्षेत्रों में अग्रता प्राप्त क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कार्य हो रहा है । भूमि सर्वेक्षण के समय इन नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रह क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले असिंचित क्षेत्रों का भी समावेश कर लिया जाता है ।

#### Central Marine Fisheries Research Institute, Mandapam

6896. SHRI MURASOLI MARAN : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is a move to shift the Central Marine Fisheries Research Institute from Mandapam ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) The Estimates Committee of the Lok Sabha in its Thirty Sixth Report has suggested that a study team consisting of representatives from the Central Government, the Institute and the concerned State Governments may be appointed to go into the question of the location of the headquarters of the Central Marine Fisheries Research Institute in all its ramifications before arriving at a final decision.

(b) The reason for this suggestion is that in Marine fisheries, which is essentially captured Fisheries, the basic research work would have to be carried out on areas of occurrence of the main fisheries and the area at Mandapam does not possess any sizeable fisheries of commercial magnitude.

#### Telephone Extension to Agaly

6897. SHRI P. VISHWAMBHARAN : SHRI MANGLATHUMADAM :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) when the telephone extension to